

आधुनिकीकरण कार्यक्रम का मदरसों के संचालन और प्रबंधन पर प्रभाव

जावेद अनीस

शोध छात्र

बरकत उल्ला वि.वि., भोपाल

सारांश

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मदरसा सुधार को लेकर कदम उठाये जाते रहे मदरसों के आधुनिकीकरण के लिये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 1998 में मदरसों में गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूलईएम) का प्रारंभ किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक विषयों से जोड़ना है जिससे मदरसा तथा मकतबों जैसी परम्परागत संस्थाओं को अपने पाठ्यक्रमों में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिन्दी तथा अंग्रेजी को शुरू करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक योजना है जिसके अंतर्गत मदरसों में आधुनिक विषयों के शिक्षण के लिये इच्छुक मदरसों को अनुदान दिया जाता है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये कई राज्यों में मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश में भी वर्ष 1998 में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है, जो मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत मदरसों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने के लिये और इनको मान्यता देने का काम करती है। मदरसों को आधुनिकीकरण कार्यक्रम से जोड़ने के लिये मदरसा बोर्ड में पंजीयन अनिवार्य है, लेकिन इसके पूर्व मदरसा संचालन समिति का गठन किया जाना चाहिये क्योंकि मदरसा पंजीयन का आवेदन समिति के अध्यक्ष या सचिव की ओर से किये जाने का प्रावधान है। इसी बिन्दु को ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत शोध पत्र में मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम का मदरसों के संचालन और प्रबंधन पर हुये प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द- मदरसा, मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम,

समाज वैज्ञानिकी अक्टूबर- मार्च 2020-21

अंक- 33-34, ISSN 0973-4201

भारतीय समाज विज्ञान परिषद्